संख्या बी-1-4208 /दस-2004-247/2004

प्रेषक,

वी.के.मित्तल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 21 सितम्बर, 2004

विषय : वर्ष 2004-2005 की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किया जाना ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2004-2005 का बजट समय से पारित होने के बाद तत्सम्बन्धी वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने के आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या संख्या-बी-1-751/दस-2004-247/2003 दिनांक 05 मार्च, 2004 द्वारा जारी किये गये थे । लेकिन यह बात संज्ञान में आयी है कि विभिन्न विकास कार्यक्रमों हेतु आयोजनागत पक्ष, विशेष रूप से जिला योजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन जनपद स्तर पर अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है । परिणामस्वरूप कतिपय विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है । यह स्थिति अत्यन्त असन्तोषजनक है ।

अतः समस्त प्रमुख सचिव / सचिव तत्काल यह सुनिश्चित कर लें कि विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन स्तर पर तत्काल धनराशि उपलब्ध हो जाय और धनराशि की अनुपलब्धता के कारण विकास कार्यक्रम प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हों । समय-समय पर जारी शासनादेशों द्वारा यह पूर्व ही स्पष्ट किया जा चुका है कि जिला योजनाओं से सम्बन्धित धनराशि सीधे जिला स्तरीय अधिकारियों के निस्तारण पर रख दी जाय । बाह्य सहायतित परियोजनाओं तथा अन्य रिसोर्स लिंक्ड परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने तथा तत्सम्बन्धी व्यय की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाय ।

जैसा कि उपरउल्लिखित वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 05 मार्च, 2004 में स्पष्ट किया गया है, जिन योजनाओं का व्यय आंशिक अथवा पूर्ण रूप से भारत सरकार अथवा विभिन्न संस्थाओं द्वारा वहन किया जाना है, उनके सम्बन्ध में यथा स्थिति योजनाओं के कार्यान्वयन की औपचारिक स्वीकृति अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में ठोस कार्यवाही की जाय ताकि तत्सम्बन्धी वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी होने में विलम्ब के कारण योजनाओं का कार्यान्वयन प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो ।

वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने के सम्बन्ध में कार्ययोजना इस प्रकार बनाई जाय कि चालू वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने की स्थिति ही उत्पन्न न हो ।

भवदीय,

(वी.के.मित्तल)
मुख्य सचिव ।